

रोजा का समय

सेहरी (08.03.2025) : 04.42 बजे

झप्तार (07.03.2025) : 05.56 बजे

Sreeleathers
66 K-ROAD, BISTUPUR

न्यूज डायरी

स्पीकर से नेता प्रतिपक्ष का मान्यता देने का आग्रह

रांची। झारखंड प्रदेश भाजपा ने विधानसभा अध्यक्ष रखीं नाथ महतो से सदन में नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्रदान करने का आग्रह घुरुवार को किया है। पाठी ने उन्हें बाबूलाल मराडी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद पत्र सौंपा और आग्रह किया। पाठी ने केंद्रीय पर्यावरक भूप्रैद यादव और डॉ के लक्ष्मण की ओर से हस्तक्षणित पत्र भी उन्हें सौंपा।

स्थिरता ही विकास की पहली गारंटी: के राजू मेंदिनीनगर। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू घुरुवार को कहा कि राज्य में सरकार के स्थायित्व को लेकर किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भाजपा निश्चित जन कल्यानकारी हिते के लिए है और यह रिता अटूट है। उन्होंने कहा कि स्थिरता किसी भी सरकार के विकास की गारंटी है और कांग्रेस का हमेस्त सोरेन को खुला समर्थन प्राप्त है। वह घुरुवार को सर्किन हास्त में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विस परिणाम के बाद पाठी जनों में उत्साह का महान है।

जयशंकर की सुरक्षा में चूक पर भड़का भारत नयी दिल्ली। विदेश मंत्री जयशंकर ब्रिटेन और आरएलैंड के छह दिनों के दौरे पर हैं। लंदन में उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीरा स्टार्मर और विदेश मंत्री डेंड लैमी से मुलाकात की। चूक टैक के कार्यकारी दल वाट जैसे ही वह बाहर निकले। खालिस्तानी झंडे लेकर कुछ लोगों ने भारत लियों ने नारेबाजी की। एक खालिस्तानी प्रदर्शनकारी ने उनकी कार का रास्ता रोक लिया। तिरंगा फाँट दिया। इस घटना की भारत के विदेश मंत्रालय ने कड़ी निया की है और ब्रिटेन के साथ राजनयिक दृष्टियों का निर्वहन करने की सलाह दी। घुरुवार को ब्रिटेन से अपनी सफाई में इस चूक की निया की। अराजकताओं को घोटाली दी कि किसी भी तरह के धमकी देने या डराने की कोशिशें अस्वीकार्य हैं।

अपील के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार चतुरा। एक गुण सूक्तना पर पुलिस ने छापमारी कर 2.2 किलो अपेक्ष अपील के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन में कई राज्यों के प्रतिनिधि जुटे।

राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर झामुमो अग्रसर अपैल महाधिवेशन

होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग खेल प्रतियोगिता का राज्यपाल ने किया शुभारंभ

खबर मन्त्र व्यूह

रांची। तीन दिवसीय झारखण्ड होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग खेल प्रतियोगिता 2025 का गुरुवार को धुवा स्थित होमगार्ड ग्राउंड पर आगाज हो चुका है। झारखण्ड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस आयोजन में अगले तीन दिनों तक झारखण्ड होमगार्ड और अग्निशमन के बेहतरीन खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे।

तीन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अधिकारी के रूप आग लिया। खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत होमगार्ड जवानों के बेहतरीन परेंट दमखम दिखाएंगे।

सीएम से मिला पुलिस में सोसाइटीएशन का प्रतिनिधिमंडल

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को आगासीय कार्यालय में झारखण्ड पुलिस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रतिनिधिमंडल व झारखण्ड पुलिस में सोसाइटीएशन के प्रतिनिधिमंडल ने शिशांग मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री का गम्भीरोंगी ने साथ अधिवाद किया। मुख्यमंत्री ने भी झारखण्ड पुलिस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित प्रतिनिधिमंडल को बधाई और शुभारंभ की साथ झारखण्ड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को बधाई दी। झारखण्ड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अगले तीन दिनों तक झारखण्ड के राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अधिकारी के रूप आग लिया। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में जारी खारखण्ड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हर पुलिस के माध्यम से जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है तिए बेहद जरूरी है। प्रतियोगिता के माध्यम से जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है।



के द्वारा शुरू की गई।

प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में जारी खारखण्ड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने अपने जवानों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता हर पुलिस के माध्यम से जवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है।

रांची विवि का 38वां दीक्षांत समारोह आज डिग्री और मेडल लेने में बेटियां फिर आगे

विवि के 63 गोल्ड पर 48 में बेटियों का कब्जा, दीक्षांत मंडप तैयार, किया गया रिहर्सल

खबर मन्त्र व्यूह

रांची। रांची विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह झुकावार को विश्वविद्यालय के मोरहावाली स्थित दीक्षांत मंडप में सुबह 11 बजे से होगा। गुरुवार को दीक्षांत शोभायात्रा कुमार, वरीय सुरुकु वरिष्ठ संतोष कुमार मरते एवं राशी कुमार पांडे, संगठन सचिव मंडू शुभा, वरीय उमायश गोहमद ब्रह्मा आलम, उमायश रोहित कुमार जगें, अलम, उमायश परमेश्वर महोनी, कृष्णायश गुलाब महोनी, सहायक महोनी लालेश्वर राम, सहायक महोनी तपेश्वर यादव के अलावा भी झुकावार द्वारा दिखाए गए।

प्रदान किया जाएगा। इस बार भी टॉपरों की सुची में छात्रों ने छात्रों को पीछे छोड़ दिया है। समारोह में 63 गोल्ड मेडल बटोरे। इनमें 48 छात्रों ने 15 छात्रों के हिस्से आए हैं। इसके अलावा 14 प्रायोजित गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। डिग्री प्राप्त करने में भी लड़कियां अच्छे हैं। समारोह में डिग्री प्राप्त करने के बाकी छात्रों को गोल्ड मेडल सरकार के द्वारा दिया जाएगा। डिग्री प्राप्त करने में भी लड़कियां अच्छी हैं। इनमें से 3291 छात्रों को संख्या 4410 है, इनमें 11 छात्रों ने फॉर्म दिखाए।

छात्र हैं।

विश्वविद्यालय के वित परामर्शी अजय कुमार ने बताया कि समारोह के मुख्य अधिकारी उपस्थित थे। बताते चले कि 1 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2025 के द्वारा प्रकाशित 6 परीक्षा परिणामों के आगर पर सफलता द्वारा दीक्षांत शोभायात्रा के टॉपरों को गोल्ड मेडल दिखायी दी जाएगी। इसके अलावा दीक्षांत मंडप में विद्यार्थियों को संख्या 4410 है, इनमें 11 छात्रों ने फॉर्म दिखाए।



उन्होंने बताया कि डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राएं ड्रेस कोड में रहेंगे। लड़कों का पहलावास-सफेर पायजामा/धोनी-कूर्ता रहेगा और लड़कियां का परिधान-लाला पाइ एवं लालाली रानी-लाला उत्तम या सफेर सलवार-कुर्ता और लाल दुप्पा रहेगा। समारोह में काले रंग के परिधान में प्रवेश वर्जित रहेगा। डीएमब्ल्यू डॉ सुदेश कुमार साहू, सीसीडीसी डॉ पीके ज्ञा, वित परामर्शी डॉ प्रियंका कुमार, ब्राह्मणी संजय से, उच्च एवं तत्कालीन नीती विधायिका डॉ विजय राजेश विभाग, झारखण्ड सरकार के मंत्री सुदित्य कुमार और वित मंत्री राधाकृष्ण किंशार मौजूद रहेंगे।

450 खिलाड़ी ले रहे हैं भाग

खेलकूद प्रतियोगिता में इस वर्ष लगभग 450 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता में 10 खेलों का आयोजन किया गया है, जिनमें एथलीट्स, कूटबॉल और वॉलीबॉल भी शामिल है। तीन दिनों तक वह प्रतियोगिता चलेगा जिसमें जवानों को अपने खेल का हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। इस मौके पर मौजूद डॉ जी होमगार्ड अग्निशमन विभाग ने बताया कि इस तरह के आयोजन हमारे जवानों के लिए बेहद आवश्यक है। हमारे जवान बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं ऐसी प्रतियोगिताएं उनके लिए बेहद जरूरी हैं।

साथ ही साथ एक दूसरे जवानों को एक स्वयं प्रतिस्पर्धा का सामना करने का भी मौका मिलता है।

बेहतरीन है यहरे जवान : झारखण्ड के होमगार्ड जवानों और अग्निशमन विभाग के जवानों को अपनी हैसला बढ़ाते हुए राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि दोनों ही फॉर्म

बेहद कठिन परिस्थितियों में काम करती है। अग्निशमन दस्ते में शामिल हमारे जवान अपनी जान पर खेलकूद आग पर काबू पाते हैं। ऐसे जवानों के हक की आवाज हमेशा उठाई जाती है हर तरफ की सुविधा देने का प्लान भी तैयार किया गया है।

राज्यपाल से मिला आइसा का डेलिगेशन शिक्षा व रोजगार के मुद्दों पर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन



खबर मन्त्र व्यूह

कॉलेजों और विवि से जुड़े प्रमुख मुद्दे

आइसा ने धनबाद के पी.के.राय कॉलेज, गोदावरी के आरएस मोर कॉलेज और पांके के एम के। कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) की पढाई जल्द शुरू करने की मांग की। इसके अलावा, मेदिनीनगर के गर्जस्टर हॉटेल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंपा।

शिक्षा सुधार और रोजगार नीति की मांग : शिष्टमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि झारखण्ड में स्थानीय विविधायिकाओं में बेहतरीन विविधायिकाओं के बीच विविधायिकाओं का विवरण दिया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। साथ ही, परिक्षा प्रमाणपत्र लीके के लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई।

छात्रों के लिए को लेकर कई अहम सुझाव : आइसा प्रतिनिधित्व के अधिकारी ने राज्यपाल से आग्रह किया कि झारखण्ड के सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराये, प्रधानिकारी द्वारा त्रैमासिक रूप से विश्वविद्यालयों में नियमित विविधायिकाओं की विवरण दिया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।

संथाली भाषा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की मांग : आइसा ने ऑलचिंचिकों की लिपि को मान्यता देने और राज्य में स्थेल अकादमी स्थापित करने की भी मांग ली।

संथाली भाषा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की मांग : आइसा ने ऑलचिंचिकों की लिपि को मान्यता देने और संथाली विविधायिकाओं में बेहतरीन विविधायिकाओं की विवरण दिया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।

संथाली भाषा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की मांग : आइसा ने ऑलचिंचिकों की लिपि को मान्यता देने और संथाली विविधायिकाओं में बेहतरीन विविधायिकाओं की विवरण दिया जाए, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।

पुलिस की लापरवाही के कारण आरोपी बरी

रांची। लोडेड पिलोल के साथ जिस पुलिस टीम आरोपी को गिरफ्तार किया था। वही पुलिस टीम अदालत में आरोपी के आरोपी को सावित करने नहीं पहुंची। आरोपी राज कुमार साहू को पुलिस ओपी के तकालीन प्रधारी विवेक कुमार ने गुप्त सूचना के अधार पर 27 जनवरी 2023 को दीपा टोली में रेसिडेन्टी के पास गिरफ्तार किया था। जांच पूरी करते हुए आईओडीब्लियूल मूर्मन ने छह पुलिस गवाहों परुंग औपी प्रधारी विवेक कुमार, ब्राह्मणी संजय कुमार, प्रावर्कर डॉ मुकुंद चंद्र मेंहता और विविधायिकारी एसएसआई धनंजय कुमार गय, आरोपी पीटर ऑडियाए सुदेशर रिंग, रमेंड तिर्की के साथ दो स्वतंत्र गवाह से पूछताल नहीं की गई और यहां तक कि जबकी गई सामग्री भी अदालत के समक्ष पेश नहीं की गई है। अधियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से निराकार है

बाल विवाह एक कलंक

पि छले एक वर्ष में दो लाख बाल विवाह कानून की सख्ती से

रोके गए। निश्चिंत रूप से बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन ही है। जिससे बच्चों तउम पढ़ाई से बचत हो जाती हैं और उनका शारीरिक तांत्रिक प्रदार्द हो जाता है। सही मायने में बाल विवाह कुपोषण एवं गरीबी का ऐसा चक्र खैरा करता है जिसका प्रभाव राष्ट्र को चुकानी पड़ती है। चौंकने वाले आकड़े हैं कि पश्चिम बंगाल, बिहार व त्रिपुरा में 40 फीसदी लड़कों के विवाह 18 साल से फहले हो जाते हैं। वहीं वज्र है कि केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अधियान की शुरूआत की है। दरअसल, यह शुरूआत उन राज्यों को लेकर की गई है, जहां बाल विवाह की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तथ्य भी कि समाज में गरीबी और बाल विवाह में सोधा रिता है। एक अध्ययन के अनुसार 75 फीसदी बाल विवाह गरीब परिवर्तों में होते हैं। जो कालांतर गरीबी के नये दुश्क्र को जन्म देते हैं। निश्चिंत रूप से डमरे समाज में गरीबी व रूढ़िवाद के चलते इस दर्शकों को बल मिलता है। अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि संपन्न, शिक्षित और प्रगतिशील समाजों में बाल विवाह के मामले सामान्यतः नज़र नहीं आते। वहीं दुर्भारी और लिंगभेद की सोच भी इन विवाहों को बढ़ावा देती चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 बहुभाषी शिक्षा को बढ़ाने और भाषाओं के विविधता की सुधार के बीच संतुलन हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण है। गैर-हिन्दी भाषी राज्यों की चिंताएं कथित भाषाओं प्रभुत्व से सम्बंधित मुद्दों और इस नीति को कार्यान्वय करने में व्यावहारिक काठिनायों पर जोर देती है। निश्चिंत का लक्ष्य बहुभाषित करना को प्रोत्साहित करना है, जिससे गरीबी और संकृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा और भारत का भाषाओं परिवर्ष सम्पद्ध होगा। उदाहरण के लिए, उत्तर भारतीय स्कूलों में तमिल पढ़ाने से सांस्कृतिक सम्बद्धी को बढ़ावा मिल सकता है और क्षेत्रीय अंतर को पाठने में मदद मिल सकती है।

अनेक भाषाओं, विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता से सरकारी नौकरियों, अनुवाद और पर्यटन में विभिन्न कैरियर के रस्ते खुलते हैं। इसके अलावा, कूटनीति और बहुराष्ट्रीय नियामों में पदों के लिए बहुभाषी कौशल अक्सर आवश्यक होते हैं। नीति वेद अनिवार्य किया गया है कि सीखने जाने वाली कम से कम दो भाषाएं भारत की मूल भाषाएं हों, जिससे देश की भाषाएं विवरण और सांस्कृतिक संरचनाएं हो सकें। देश की शास्त्रीय और क्षेत्रीय भाषाओं परिषरों को बनाए रखने के लिए संकृत, बंगाली, तेलुगु और मराठी जैसी भाषाओं का प्रचार-प्रसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे

राज्यों की लिंगभेद की सोच भी इन विवाहों को बढ़ावा देती है।

राज्य हिन्दी की अपेक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिसके साथ उनका सम्बंध टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली-अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अनिवार्य हिन्दी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में, विशेषकर अर्थात् रूप से विविध राज्यों में, अक्सर भाषा शिक्षकों, सासाधनों और डिजिटल भाषा प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक धन की कमी होती है।

2020 की लीन-भाषा आवश्यकता का पालन नहीं करने का विकल्प चुना है, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के लिए समग्र शिक्षा अधियान के तहत विविध धनों में दोरी हो रही है।

इसके अतिरिक्त, कई राज्यों को इन अतिरिक्त भाषाओं के लिए व्याय शिक्षकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में कार्यान्वयन जटिल हो रहा है। उदाहरण के लिए, औडिशा और केरल के स्कूलों को समिति उपलब्धता के कारण हिन्दी शिक्षकों को ढंगने में संघर्ष में पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में बंगाली-अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अनिवार्य हिन्दी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में, विशेषकर अर्थात् रूप से विविध राज्यों में, अक्सर भाषा शिक्षकों का सामिल करना चाहिए ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वह स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। संयुक्त शिक्षा समिति की स्थापना से राज्यों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में अधिक आवाज मिल सकती है। यूजीसी संस्कृत, पाली और फरसी में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। क्रैंक ग्रामीण छात्रों को सूसीरी भाषा सीखने में कठिनाई होती है, जिससे तीसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया है।

जटिल हो जाती है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण विवाद में देखते हैं, जिसके अक्सर इन नीतियों को अपने स्थानीय शासन अंदर समर्पित विषय है, इसलिए केंद्रीकृत भाषा सीखने की नीति लागू करना संघीय सिद्धांतों के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है। तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-

राज्यों के लिए एक मानकीकृत त्रिभाषा नीति का पालन करने की बजाय अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनौते की स्वतंत्रता होना अधिक लाभदायक होगा। उदाहरण के लिए, कर्नाटक सरकार हिन्दी लागू करने के बजाय अपनी भाषा प्रयोगशाला पहले से दीप्रौद्योगिकी के माध्यम से स्थानीय भाषा शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रतिष्ठित कर सकती है। शिक्षक प्रशिक्षण की स्थानीय भाषा शिक्षा के लिए एक अधिकारी और लैपटॉप जैसे गैजेट्स भी खतरा बन गए हैं। इसका नाम एक नुकसान पहुंचाने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है, वह न एक साइबर हालात लागू करने के बजाय कन्नड़, अंग्रेजी और विद्यार्थी की पसंदीदा की भाषा पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, ई-लैर्निंग संसाधनों का विकास करना, तथा भाषा अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना स्थिति में काफी सुधार ला सकता है।

अंध्र प्रदेश नीति के लिए एक मानकीकृत त्रिभाषा नीति का पालन करने की बजाय अपनी क्षेत्रीय भाषा चुनौते की स्वतंत्रता होना अधिक लाभदायक होगा। उदाहरण के लिए, कर्नाटक सरकार हिन्दी लागू करने के बजाय कन्नड़, अंग्रेजी और विद्यार्थी की पसंदीदा की भाषा पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक मानकीकृत त्रिभाषा नीति का पालन करना चाहिए।

राज्य हिन्दी की अपेक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे कार्यान्वयन के साथ उनका सम्बंध टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली-अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अनिवार्य हिन्दी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में, विशेषकर अर्थात् रूप से विविध राज्यों में, अक्सर भाषा शिक्षकों, सासाधनों और डिजिटल भाषा प्रयोगशालाओं के लिए आवश्यक धन की कमी होती है।

राज्य हिन्दी की अपेक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनकी साथ उनका सम्बंध टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली-अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अनिवार्य हिन्दी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में, विशेषकर अर्थात् रूप से विविध राज्यों में, अक्सर भाषा शिक्षकों का सामिल करना चाहिए ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वह स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। संयुक्त शिक्षा समिति की स्थापना से राज्यों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में अधिक आवाज मिल सकती है। यूजीसी संस्कृत, पाली और फरसी में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। क्रैंक ग्रामीण छात्रों को सूसीरी भाषा सीखने में कठिनाई होती है, जिससे तीसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया है।

राज्य हिन्दी की अपेक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनकी साथ उनका सम्बंध टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली-अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अनिवार्य हिन्दी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में, विशेषकर अर्थात् रूप से विविध राज्यों में, अक्सर भाषा शिक्षकों का सामिल करना चाहिए ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वह स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। संयुक्त शिक्षा समिति की स्थापना से राज्यों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में अधिक आवाज मिल सकती है। यूजीसी संस्कृत, पाली और फरसी में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। क्रैंक ग्रामीण छात्रों को सूसीरी भाषा सीखने में कठिनाई होती है, जिससे तीसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया है।

राज्य हिन्दी की अपेक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनकी साथ उनका सम्बंध टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली-अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अनिवार्य हिन्दी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में, विशेषकर अर्थात् रूप से विविध राज्यों में, अक्सर भाषा शिक्षकों का सामिल करना चाहिए ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि वह स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। संयुक्त शिक्षा समिति की स्थापना से राज्यों को कार्यान्वयन प्रक्रिया में अधिक आवाज मिल सकती है। यूजीसी संस्कृत, पाली और फरसी में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। क्रैंक ग्रामीण छात्रों को सूसीरी भाषा सीखने में कठिनाई होती है, जिससे तीसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया है।

राज्य हिन्दी की अपेक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हैं, जिससे उनकी साथ उनका सम्बंध टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में बंगाली-अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है तथा अनिवार्य हिन्दी शिक्षा को अस्वीकार कर दिया जाता है। स



आवास लाइसेंसिंग
योजना के लिए 8 नार्च से
आवेदन आमंत्रित

बोकारो। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा आवास लाइसेंस योजना लाई जा रही है जिसमें वैसे पूर्व कर्मचारी आवेदन जमा कर सकते हैं जैसे इन प्रकार के आवास में रह रहे हैं तथा आवास को लाइसेंस पर लेने के इच्छुक हैं। इसके अलावा वैसे कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे जो जून-हृष्ट 2025 तक संवानित होंगे और वर्तमान में इन प्रकार के आवास में रह रहे हैं।

